दौरान हुए निर्यात से कम था । 1998-99 के दौरान (अक्तूबर, 1998 तक) हुए निर्यात पर प्रोदभूत कुल आए पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 11.36 करोड़ रू0 की आय की तुलना में 4.14 करोड़ रू0 थी ।

कोयला खानों की रायल्टी का पुन: निर्धारण

319. **श्री रामजीलाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोयला खदानों की रायल्टी के पुनर्निधारण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कोककर कोयले और "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की आधार कीमतों के 25 प्रतिशत और "डी", "ई" "एफ" और "जी" ग्रेड अकोककर कोयले की कीमतों के 20 प्रतिशत तक कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया है । पिछले वर्षो में आयातित कोयलेकी तुलना में भारतीय कोयले की उत्पादन लागत कम है, फिर भी उच्च भाड़ा-शुल्क और उच्च रॉयल्टी लेवी के कारण देश में भारतीय कोयले की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हो गयी है । इस परिप्रेक्ष्य में रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया जाएगा ।

Amendment lo Coai Mines (Nationalisation) Act, 1973

320. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to move amendments to the Coal Mines (Nationalisation) Act. 1973 in the direction of privatisation of coal mines;

(b) if so, whether Government held discussions with the Trade Unions which are against Government's move;

(c) it so, the details thereof; and

(d) if not, tbe reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) The Ministry of Coal propose the make amendment to Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 to allow coal mining by Indian companies without existing restriction of captive consumption. The proposal does not involve privatisation of any of the existing coal mines of Coal India Limited (CIL) or of Singareni Collieries Company Limited (SCCL).

(b) and (c) The proposal was discussed wirti the Trade Unions on several occasions. While the unions recognised that a demand supply gap will remain at the end of the IX Plan, they insisted that increased production by the nationalised coal companies should be made possible by increasing budgetary support to them. It was explained to them that provision of budgetary support to CIL has been stopped since 1995-96 and it is not possible to restore the support.

(d) Does not arise in view of the answer given to paras (b) and (c) of the Question.

कोयले पर रायल्टी

320. **श्री नरेश यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों की ओर से कोयले पर रायल्टी के रूप में देयताओं की अदायगी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इन अनुरोधों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार को विद्यमान दरों के अनुसार कोयले पर रायॅल्टी के रूप में देय बकाया राशि का भुगतान किए जाने के लिए राज्य सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकारों की ओर देय रायॅल्टी की राशि की वसूली कोयला कंपनियों द्वारा

कोयला उपभोक्ताओं से की जाती है और उसका भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न की नहीं उठता है।

Interest burden on Singareni Collieries

322. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether large interest burden has fallen on the Singareni Collieries Company Ltd. during the Eighth Five Year Plan;

(b) whether the Government of Andhra Pradesh has requested Government to waive this interest burden to make Singareni Collieries functioning more effectively; and

(c) if so, the response of Government towards the request of the Andhra Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of Andhra Pradesh have requested the Ministry of Coal or waiver of the outstanding interest of Rs. 663.34 crores due from Singareni Collieries Company Limited (SCCL) which had accrued during the VIII Plan period on the loans from Government of India. A restructuring package including revision of the equity-debt structure of SCCL and the request of the State Government for waiver of the outstanding interest is under consideration of the Ministry of Coal.

वर्ष 1999 को "सैनिक वर्ष" के रूप में मनाया जाना

323. **श्री कपिल सिब्बल :**

श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी वर्ष अर्थात् 1999 को "सैनिक वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मनाने के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के लिए क्या योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) इस सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सियाचिन पर भारत-पाक वार्ता

324. **श्री जे0 चितरंजन** :

श्री जनेश्वर मिश्र :

श्री गुरूदास दासगुप्ता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सियाचिन पर भारत-पाक वार्ता विफल हो गई है,

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के मुख्य मुद्दे क्या थे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि सियाचिन जैसे दुर्गम, दुरूह और कठोर स्थान पर सैनिक चौकी रखना काफी कष्टसाध्य एवं धनसाध्य काम है, और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार भविष्य में भी इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सियाचिन समस्या को पाकिस्तानी प्राधिकारियों से बातचीत के माध्यम सेहल करने के लिए सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। हाल ही में, भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच दुबारा 6 नवबंर, 98 को नई दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक के दौरान बातचीत बेबाक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। दोनों पक्षों ने इस मामले पर अपने-अपने विचार रखे। अगले दौर की वार्ता में इस मामले पर बातचीत जारी रखने पर सहमति हुई।

सियाचिन का इलाका चाहे जिस किस्म का हो, भारतीय सेना की वहां मौजूदगरी राष्ट्रीय सुरक्षा की परम आवश्यकता है।